http://krishipravahika.vitalbiotech.org/
e-ISSN: 2583 – 0430
कृषि-प्रवाहिका: ई-समाचार पत्रिका, (2024) वर्ष 4, अंक 12, 5-9
Article ID: 415

कृषि में माइक्रो फाइनेंस और स्वयं सहायता समूहों की भूमिका

पवन सालवी एंव मनोज कुमार

पशु उत्पादन विभाग, राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान, भारत

1. प्रस्तावना

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और उनकी आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। किंतु कृषि के क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों की कमी, तकनीकी जानकारी का अभाव तथा बाजार तक सीमित पहुंच जैसी समस्याएं किसानों को निरंतर प्रभावित करती रही हैं। ऐसे में ''माइक्रो फाइनेंस'' और ''स्वयं सहायता समूह Self Help Groups & SHGs जैसे वैकल्पिक वित्तीय और सामुदायिक उपाय ग्रामीण विकास और कृषि सुधार की दिशा में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं। माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा उन गरीब और सीमांत किसानों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने का प्रयास करती है जिन्हें पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली द्वारा सेवाएं प्राप्त नहीं हो पाती। वहीं, स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं और किसानों को संगठित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम बन चुके हैं। इस लेख में हम कृषि के क्षेत्र में माइक्रो फाइनेंस और स्वयं सहायता समूहों की भूमिका, प्रभाव और संभावनाओं का विश्लेषण करेंगे।

2. माइक्रो फाइनेंस की परिभाषा और उद्देश्य

माइक्रो फाइनेंस का अर्थ छोटे स्तर पर वित्तीय सेवाएं जैसे कि ऋण, बीमा, बचत, और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य उन ग्रामीण गरीबों और सीमांत किसानों तक वित्तीय संसाधन पहुंचाना है जो पारंपरिक बैंकों की जटिल प्रक्रियाओं या गारंटी व्यवस्था के कारण ऋण प्राप्त नहीं कर पाते। माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं जैसे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एनबीएफसी स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलकर काम करती हैं और किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती हैं। इससे वे उन्नत बीज, खाद, सिंचाई उपकरण, और कृषि तकनीकें अपनाकर अपनी कृषि उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा, आपातकालीन आवश्यकताओं जैसे चिकित्सा, शिक्षा या सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए भी यह वित्तीय सहारा प्रदान करता है। माइक्रो फाइनेंस का उद्देश्य न केवल आर्थिक सहायता देना है, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण और ग्रामीण समुदायों की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना भी है।

3. स्वयं सहायता समूहों की अवधारणा

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) छोटे समूह होते हैं जिनमें सामान्यतः 10 से 20 सदस्य होते हैं, विशेषकर महिलाएं। ये सदस्य नियमित रूप से धन इकट्ठा करते हैं और समूह में से जरूरतमंदों को ऋण देते हैं। यह प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित होती है। इन समूहों का मुख्य उद्देश्य सामूहिक बचत और ऋण व्यवस्था के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण करना होता है। एसएचजी का गठन विशेष रूप से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने, उनकी सामाजिक स्थिति को सशक्त करने और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में एसएचजी किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण, बाजार से जुड़ाव, सरकारी योजनाओं का लाभ तथा सामूहिक खेती जैसे कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत ये समूह बैंकों से जुड़कर औपचारिक ऋण भी प्राप्त कर

सकते हैं जिससे वे अपने कृषि या गैर-कृषि व्यवसायों को विस्तार दे सकते हैं।

4. एसएचजी और माइक्रो फाइनेंस का आपसी संबंध

स्वयं सहायता समूह और माइक्रो फाइनेंस आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। एसएचजी समूहों के माध्यम से माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं बगैर किसी जमानत के ऋण वितरण कर सकती हैं, क्योंकि समूह सामूहिक रूप से ऋण की वापसी के लिए उत्तरदायी होता है। यह प्रणाली ऋण की वापसी दर को अत्यधिक बढ़ा देती है, जिससे वित्तीय संस्थाओं का विश्वास भी बना रहता है। एसएचजी के सदस्य ऋण लेकर कृषि यंत्र खरीदने, बीज व खाद्य सामग्री खरीदने, पशुपालन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन आदि में निवेश करते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर बढ़ते हैं और पलायन में भी कमी आती है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जैसे कि SKS Microfinance] BASIX और बैंकिंग संस्थाएं एसएचजी से जुड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ा रही हैं। इस साझेदारी से जहां एसएचजी को वित्तीय शक्ति मिलती है, वहीं माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को भरोसेमंद उधारकर्ता समूह मिलते हैं।

5. कृषि ऋण की पहुंच में सुधार

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए ऋण प्राप्त करना लंबे समय से एक चुनौती रही है। बैंकों की जटिल प्रक्रिया, जमानत की आवश्यकता, और दस्तावेजों की कमी के कारण छोटे और सीमांत किसान पारंपरिक ऋण व्यवस्था से वंचित रहते हैं। ऐसे में माइक्रो फाइनेंस और एसएचजी एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं, जो किसानों को सरल और त्वरित तरीके से ऋण प्रदान करने में सहायक होते हैं। माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं बिना किसी संपत्ति की मांग किए, न्यूनतम औपचारिकताओं के साथ ऋण देती हैं। एसएचजी के माध्यम से महिलाएं या परिवार सामूहिक रूप से बैंकों से जुड़कर कृषि आवश्यकताओं जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई उपकरण आदि के लिए ऋण प्राप्त करती हैं। इससे न केवल कृषि उत्पादन बढ़ता है, बल्कि किसान ऋण के लिए साहूकारों के चंगुल से भी बचते हैं। इसके अलावा, एसएचजी सदस्यों को वित्तीय साक्षरता, ऋण प्रबंधन और बचत की शिक्षा भी दी जाती है जिससे वे अपने वित्तीय निर्णय अधिक समझदारी से ले पाते हैं।

6. महिला सशक्तिकरण में भूमिका

कृषि में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, फिर भी उन्हें अक्सर आर्थिक निर्णयों से दूर रखा जाता है। एसएचजी और माइक्रो फाइनेंस महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हैं, बल्कि उन्हें नेतृत्व, निर्णय-निर्धारण और उद्यमिता में भाग लेने के लिए प्रेरित भी करते हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं सामूहिक रूप से बचत करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऋण लेती हैं। इससे वे घरेलू आवश्यकताओं के साथ-साथ कृषि से जुड़े कार्यों जैसे सब्जी उत्पादन, पशुपालन, बागवानी, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन आदि में भी निवेश करती हैं। इससे न केवल उनके परिवार की आय में वृद्धि होती है, बल्कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति और आत्मविश्वास में भी सुधार होता है। कई एसएचजी महिलाएं अब अपने क्षेत्र में रोल मॉडल बन चुकी हैं जो अन्य महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं। माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार, प्रशिक्षण और बाजार से जुड़ने का अवसर भी मिलता है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनती हैं।

7. कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा

माइक्रो फाइनेंस और एसएचजी मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्यमिता Agri&entrepreneurship को बढ़ावा देते हैं। जब किसानों को ऋण उपलब्ध होता है तो वे पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों की ओर भी ध्यान देते हैं। जैसे, टमाटर की प्रोसेसिंग कर सॉस बनाना, दूध को प्रोसेस कर पनीर बनाना, या गेहूं से आटा चक्की चलाना आदि। SHG समूह सामूहिक रूप से कृषि आधारित लघु उद्योग जैसे जैविक खाद निर्माण, बीज वितरण, कुक्कुट पालन इकाइयाँ आदि प्रारंभ करते हैं। ये इकाइयाँ स्थानीय रोजगार सृजन का भी

माध्यम बनती हैं। सरकार और गैर-सरकारी संस्थाएं इन समूहों को प्रशिक्षण, उपकरण और विपणन सहायता भी प्रदान करती हैं जिससे उनकी उद्यमशीलता को विस्तार मिलता है। ग्रामीण युवाओं को इससे स्थानीय स्तर पर काम करने के अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे पलायन में भी कमी आती है।

8. सरकारी योजनाओं से समन्वय

भारत सरकार ने ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) दीनदयाल अंत्योदय योजना, महिला कोष योजना आदि। इन योजनाओं में एसएचजी और माइक्रो फाइनेंस को मुख्य भागीदार बनाया गया है। NRLM के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ा जाता है और उन्हें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, और बाजार से जोड़ने के लिए सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत भी छोटे और सीमांत किसानों को बिना गारंटी के ऋण प्रदान किए जाते हैं। एसएचजी समूह इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपने समूह सदस्यों के लिए रोजगार, प्रशिक्षण और पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। एसएचजी की संरचना इस प्रकार की जाती है कि वह सरकारी अधिकारियों, बैंकों और NGO के साथ समन्वय बनाकर योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा सके। इससे न केवल योजनाओं की पहुँच बेहतर होती है, बल्कि ग्रामीण समुदाय का विकास भी सुनिश्चित होता है।

9. ऋण पुनर्भुगतान और विश्वसनीयता

एसएचजी और माइक्रो फाइनेंस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता उनकी ऋण पुनर्भुगतान की उच्च दर है। जहां पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली में ऋण डिफॉल्ट की दर अधिक होती है, वहीं एसएचजी आधारित माइक्रो फाइनेंस में यह दर बहुत कम होती है। इसका कारण सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना है। जब कोई सदस्य ऋण लेता है, तो पूरा समूह उसकी जिम्मेदारी लेता है। यदि कोई सदस्य समय पर ऋण नहीं चुकाता है, तो समूह के अन्य सदस्य उसे प्रेरित करते हैं या उसकी ओर से राशि अदा करते हैं। यह सामूहिक सहयोग प्रणाली न केवल वित्तीय अनुशासन को बढ़ाती है, बल्कि समूह की विश्वसनीयता को भी बनाए रखती है। बैंक और अन्य संस्थाएं एसएचजी से जुड़कर अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण प्रदान करती हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि समूह ऋण की अदायगी सुनिश्चित करेगा। एसएचजी की यह पारदर्शिता और अनुशासन प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को मजबूत बनाती है।

10. कृषि तकनीक के प्रसार में भूमिका

ैएसएचजी और माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं केवल वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करतीं, बल्कि आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रचार-प्रसार में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आज के समय में कृषि में सफलता पाने के लिए केवल पारंपरिक विधियों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। किसानों को उन्नत बीज, सिंचाई तकनीक, मृदा परीक्षण, जैविक खेती, कीट प्रबंधन और फसल चक्र जैसे विषयों की जानकारी आवश्यक होती है। एसएचजी समूहों के माध्यम से कृषकों को प्रशिक्षण शिविरों, कार्यशालाओं और फील्ड विजिट्स के जरिए नई तकनीकों से अवगत कराया जाता है। माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं इन तकनीकों को अपनाने के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करती हैं। इस तरह किसान अधिक उत्पादन कर पाते हैं और उनकी आय में वृद्धि होती है। कुछ एसएचजी समूह तो ड्रिप इरिगेशन, पॉलीहाउस खेती और मोबाइल-ऐप आधारित कृषि सलाह जैसी उन्नत तकनीकों का भी सफलतापूर्वक प्रयोग कर रहे हैं।

11. विपणन और बाजार से जुड़ाव

किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वे अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं प्राप्त कर पाते। एसएचजी समूहों के माध्यम से किसान सामूहिक रूप से उपज बेचते हैं जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हो जाती है और उन्हें सीधा लाभ मिलता है। कुछ एसएचजी तो खुद का उत्पादन संग्रहीत करने के लिए कोल्ड स्टोरेज, मंडी या स्वयं की विक्रय

इकाई भी संचालित करते हैं। माइक्रो फाइनेंस से मिली सहायता से वे ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग और ब्रांडिंग जैसी सुविधाओं का उपयोग कर पाते हैं। एसएचजी समूह अक्सर एफपीओ (Farmer Producer Organçation) के रूप में संगठित होते हैं जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और बड़े बाजारों तक सीधी पहुंच प्राप्त होती है। ऑनलाइन पोर्टल्स और डिजिटल भुगतान प्रणाली ने इस प्रक्रिया को और सरल और पारदर्शी बना दिया है। इससे न केवल उत्पाद की कीमत बढ़ती है, बल्कि किसानों का आत्मविश्वास और समझ भी बढ़ती है।

12. जलवायु परिवर्तन और कृषि जोखिम प्रबंधन

जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि कार्यों में अनिश्चितता और जोखिम बहुत बढ़ गए हैं। वर्षा की अनियमितता, तापमान में अत्यधिक वृद्धि या गिरावट, सूखा या बाढ़ जैसी परिस्थितियाँ किसानों को आर्थिक संकट में डाल सकती हैं। ऐसे में एसएचजी और माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं किसानों को जोखिम प्रबंधन में सहायता करती हैं। बीमा योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपदा राहत कोष और आपातकालीन ऋण सहायता जैसी सुविधाएं किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं। एसएचजी समूहों के माध्यम से किसानों को इस प्रकार की योजनाओं की जानकारी दी जाती है और उन्हें इन योजनाओं में नामांकित किया जाता है। इसके अलावा, एसएचजी समूहों द्वारा सामूहिक जल प्रबंधन, वृक्षारोपण, जैविक खेती जैसे पर्यावरण हितैषी उपाय अपनाए जाते हैं जो दीर्घकालिक कृषि स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। इन प्रयासों से न केवल पर्यावरण की रक्षा होती है, बल्कि कृषि प्रणाली भी लचीली और टिकाऊ बनती है।

13. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान

एसएचजी और माइक्रो फाइनेंस का प्रभाव केवल कृषि तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर डालता है। जब किसान आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं, तो वे अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करते हैं, घरेलू उपभोग में वृद्धि करते हैं और अन्य स्थानीय व्यापारों को भी समर्थन देते हैं। एसएचजी सदस्य विभिन्न गतिविधियों जैसे सिलाई, कढ़ाई, बकरी पालन, खाद्य प्रसंस्करण आदि में भी निवेश करते हैं जिससे आय के नए स्रोत उत्पन्न होते हैं। ग्रामीण स्तर पर लघु उद्योग और सेवा क्षेत्र का विकास होता है। एसएचजी सदस्यों की सामूहिक क्रय शक्ति बढ़ती है जिससे बाजार में मांग और स्थानीय व्यापारियों को लाभ होता है। यह चक्र पूरे ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को गति देता है और समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त करता है।

14. सामाजिक परिवर्तन और समावेशी विकास

एसएचजी और माइक्रो फाइनेंस ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने के सशक्त साधन बन चुके हैं। आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ सामाजिक असमानताओं में भी कमी आती है। महिला एसएचजी के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है, बाल विवाह, घरेलू हिंसा और अशिक्षा जैसी समस्याओं में भी सुधार होता है। एसएचजी समूह सामाजिक मुद्दों पर सामूहिक रूप से कार्य करते हैं और गांव में नेतृत्व प्रदान करते हैं। वे पंचायतों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों से तालमेल कर ग्राम विकास की दिशा में योगदान देते हैं। आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्गों के लोगों को एसएचजी के माध्यम से सामाजिक मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है। इस समावेशी विकास मॉडल में सबकी भागीदारी सुनिश्चित होती है और लोकतांत्रिक ढांचे को भी मजबूती मिलती है। एसएचजी की यही ताकत है कि वह व्यक्ति के साथ-साथ समाज को भी बदलने की क्षमता रखता है।

15. चुनौतियाँ और सुधार की संभावनाएँ

हालांकि एसएचजी और माइक्रो फाइनेंस ने कृषि और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, फिर भी कुछ चुनौतियाँ हैं जिन्हें सुलझाना आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में एसएचजी केवल कागजों तक सीमित हैं या सही प्रशिक्षण के अभाव में निष्क्रिय हो जाते हैं। कुछ संस्थाएं अत्यधिक

ब्याज दर वसूलती हैं या ऋण शोषण की शिकायतें सामने आती हैं। कई एसएचजी सदस्यों को उचित वित्तीय साक्षरता नहीं होती जिससे वे ऋण का सदुपयोग नहीं कर पाते। इसके अलावा, तकनीकी सहायता, बाजार जानकारी, ब्रांडिंग और लॉजिस्टिक्स की सुविधा की कमी भी उनके विकास में बाधा बनती है। इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार, बैंक, NGO और माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा। डिजिटल शिक्षा, मोबाइल बैंकिंग, पारदर्शी ऋण प्रणाली और निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए एसएचजी और माइक्रो फाइनेंस की प्रभावशीलता को और बढ़ाया जा सकता है।

निष्कर्ष

एसएचजी और माइक्रो फाइनेंस प्रणाली ने भारत के ग्रामीण परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता को सिद्ध किया है। इन दोनों ने मिलकर न केवल कृषि क्षेत्र को आर्थिक संबल प्रदान किया है, बल्कि महिलाओं, किसानों, युवाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी एक नया आत्मविश्वास और पहचान दी है। माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से जहाँ ग्रामीण समुदायों को सरल और सुलभ वित्तीय सेवाएं प्राप्त हुईं, वहीं एसएचजी ने उन्हें संगठित कर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया। भविष्य में यदि इन दोनों प्रणालियों को और अधिक पारदर्शिता, तकनीकी सहयोग और नीति समर्थन मिले, तो वे ग्रामीण विकास के सबसे प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। भारत जैसे देश में, जहाँ अधिकांश जनसंख्या कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, एसएचजी और माइक्रो फाइनेंस की भूमिका एक सामाजिक-आर्थिक क्रांति का आधार बन सकती है। यह आवश्यक है कि हम इन प्रयासों को केवल वित्तीय सहायता तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें ग्रामीण भारत के समग्र विकास के एक सशक्त माध्यम के रूप में देखें।